DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक जागरण | नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2022 | ----------DATED----------

आजादी के 75 साल बाद भी सीवर की मैनुअल सफाई दुर्भाग्यपूर्ण

- हाई कोर्ट ने कहा, मृतकों के स्वजन को दस-दस लाख मुआवजा दे डीडीए
- अनुपालन नहीं होने पर डीडीए उपाध्यक्ष को पेश होने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण हुई दो लोगों की मौत की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब कर्मचारियों को मैनुअल तरीके से सीवर की सफाई करने को मजबूर किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी इससे जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है।

उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पीड़ित परिवारों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ ही 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में डीडीए उपाध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश हों। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

पीठ ने कहा कि डीडीए ने प्रथम दृष्टया मुआवजे का भुगतान करने का संकल्प लिया है। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी।

कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन पहले मुआवजा दें : डीडीए की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि बिना किसी निर्देश के सीवर की सफाई की जा रही थी। घटना के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। डीडीए के किसी भी अधिकारी ने सीवर साफ करने को नहीं कहा था। इस पर पीठ ने कहा कि यह किसने किया और किसी जिम्मेदारी है यह बाद में तय किया जा सकता है। अधिकारी इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप प्राथमिकी दर्ज कराएं और कार्रवाई करें, लेकिन पहले मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति करें। वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा कि अधिकारियों में संवेदनशीलता की कमी है और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

द्वारका में फुटपाथ के नीचे बह रहे नाले में गिरी महिला, मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : द्वारका में गहरे नाले पर बने फुटपाथ के टूटे स्लैब जानलेवा साबित हो रहे हैं। सेक्टर-13 में फुटपाथ पर चल रही एक महिला अचानक टूटे स्लैब के कारण नाले में जा गिरी। हादसे में उनकी मौत हो गई। महिला का नाम सुधा देवी है। वे सेक्टर-15 स्थित भरत विहार में परिवार के साथ रहती थीं। स्वजन ने इसके लिए डीडीए को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हादसा बुधवार शाम करीब सात बजे का है। सुधा सेक्टर-13 में मेला देखने जा रही थीं। वे फुटपाथ पर चल रही थीं। टूटे स्लैब के कारण वे नाले में जा गिरीं। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। स्वजन ने बताया कि जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, वे दम तोड़ चुकी थीं। सुधा घरेलू सहायिका का काम करती थीं।

डीडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: डीडीए की कार्यप्रणाली को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले मुंडका थाना क्षेत्र स्थित लोकनायक पुरम में सीवर की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में भी डीडीए के अधिकारी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से बचते रहे हैं।

हिन्दुस्तान

मृतक आश्रितों को मुआवजा दे डीडीए

नई दिल्ली, प्र.सं.। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डीडीए को उन दो लोगों के परिजनों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी बीते महीने सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने डीडीए, जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई थी को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि डीडीए को इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2022

NAME OF NEWSPAPERS ...री। कोटला मुबारकपुर। छज्जूपुरा। साकेत। उत्तम नगर। पीतमपुरा

धूल के खिलाफ अभियान शुरू, होगी सख्ती

586 टीमें करेंगी निगरानी, उल्लंघन पर होगा भारी जुर्माना

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 एंटी डस्ट नियमों को लागू करना जरूरी है। एंटी डस्ट अभियान के तहत 586 टीमों का गठन किया गया है। इसमें डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल हैं।

कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है। इसमें 12 संबंधित विभागों की टीमें भी शामिल हैं। इन टीमों में डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी) की 33 टीमें, राजस्व विभाग की 165 टीमें, एमसीडी की 300, डीएसआईआईडीसी की 20, दिल्ली जल बोर्ड की 14, डीडीए की 33, दिल्ली मेट्रो की 3, सीपीडब्ल्यूडी की 6, पीडब्लूडी की 6, एनडीएमसी की 1, दिल्ली कैंट बोर्ड की 4 और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं। ये टीमें लगातार निर्माण साइट्स का दौरा करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन हो। निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है, जिसके लिए एंटी डस्ट अभियान गुरुवार से शुरू हो गया है।

एंटी डस्ट अभियान के तहत निगरानी रखने के लिए 586 टीमों का गठन किया गया

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 6 अक्टूबर से शुरू यह अभियान 6 नवंबर तक चलेगा

पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि जो भी साइट डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगी, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन मिलने पर उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद उल्लंघन हुआ तो निर्माण साइट को बंद कर दिया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन के लिए नियम

- निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए टीन की ऊंची दीवार खड़ी करना जरूरी है।
- धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर ही एंटी स्मोग गन लगाने का नियम था। अब 5 हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक के एरिया के साइट पर एंटी स्मोग गन लगाना अनिवार्य होगा। 5 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर की साइट पर 1 एंटी स्मॉग गन, 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर पर 2, 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर पर 3 और 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर की निर्माण साइट पर कम से कम 4 एंटी स्मॉग गन होनी चाहिए।
- निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को तिरपाल या नेट से ढकना जरूरी है।
- निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री लाने और ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी है।
- निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी है।
- निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिह्नित जगह पर ही डालना जरूरी है, सड़क के किनारे उसके भंडारण पर प्रतिबंध है।
- किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी-बालू को बिना ढके नहीं रखना है।

आजादी के 75 साल बाद भी गरीबों को मैला ढोने के लिए मजबूर किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण : HC

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

उन दो लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी पिछले महीने मुंडका इलाके में सीवर की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अफसोस जताते हुए गुरुवार को कहा कि यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोग हाथ से मैला ढोने का काम करने को मजबूर हैं और इसके के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने डीडीए को उन दो लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी पिछले महीने मुंडका इलाके में सीवर की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अनुपालन रिपोर्ट पर गौर किया जिसके मुताबिक घटना डीडीए के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में हुई थी। कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वह कानून के मुताबिक तत्काल और अनिवार्य रूप से मृतक के परिजनों को मुआवजे का भुगतान करे। कोर्ट ने अपने आदेश में डीडीए से यह भी कहा कि उसे इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार भी करना चाहिए।

कोर्ट ने चार हफ्तों के भीतर आदेश पर अमल की उम्मीद जताते हुए साफ किया कि इसके अनुपालन में नाकाम रहने पर डीडीए के वाइस प्रेसिडेंट व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने हाजिर हों। 9 सितंबर को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर की सफाई के लिए उतरे एक सफाई कर्मी और उसे बचाने गए सुरक्षा कर्मी की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इससे जुड़ी खबर के आधार पर कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया और इस पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की।

फुटपाथ पर चल रही महिला नाले में गिरी, मौत

■ **विस, द्वारका :** मेला घूमने जा रहीं एक महिला की फुटपाथ के नीचे बह रहे नाले में गिरकर मौत हो गई है। हादसा द्वारका सेक्टर-13 का है। जानकारी के अनुसार महिला का नाम सुधा देवी (56) है। मृतक महिला भरत विहार में परिवार के साथ रहती थीं। परिजनों ने महिला की मौत के लिए डीडीए की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा बुधवार शाम करीब 7 बजे का है। सुधा सेक्टर-13 में मेला देखने जा रहीं थीं। वह फुटपाथ पर चल रहीं थीं। अंधेरे की वजह से उन्हें फुटपाथ पर टूटा स्लैब नजर नहीं आया। इसकी वजह से वह नाले में गिर गईं। आसपास मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि जब तक महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता, वह दम तोड़ चुकी थीं।

अंधेरे में फुटपाथ का टूटा स्लैब महिला को दिखाई नहीं दिया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, OCTOBER 7, 2022

DDA to pay ₹10 lakh each to kin of 2 workers who died in sewer: HC

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Lamenting that poor people are forced to work as manual scavengers "even after 75 years of Independence", the Delhi high court on Thursday ordered Delhi Development Authority to pay Rs 10 lakh each to the family of two men who died in a sewer last month.

The court had taken suo motu cognizance of a **TOI** report and initiated a PIL, putting the civic agencies and Delhi government on notice to explain why the deaths took place and what steps are being taken to prevent similar incidents.

Brushing aside claims by DDA that the victims were not on its roll and it had not given instructions to them to clean the sewer, the court made it clear that the buck stopped with the agency since the area fell under its jurisdiction. A bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad added that DDA shall also consider granting compassionate appointment to a family member of the dead men.

HIGH COURT OBSERVED

It is unfortunate that even after 75 years of Independence, poor people are forced to work as manual scavenger and the laws are not being followed

"It is unfortunate that even after 75 years of Independence, poor people are forced to work as manual scavenger and the (laws on the issue) are not being followed....as DDA has prima facie resolved to pay compensation, keeping in view the judgement of the Supreme Court, DDA is directed to pay Rs 10 lakh each as compensation to the family of the two deceased and also to consider their claim to grant compassionate appointment in terms of the Supreme Court judgement and statutory provisions," the HC observed.

The court further noted that DDA has to inform it of the decision in 30 days. "If the order is not complied with, the vice-chairman of DDA shall remain present in court on the next date of hearing," it cautioned.

DDA in its reply stated that a committee has been formed to investigate the incident. It argued that "not a single DDA official recommended" the victims to clean the sewer. The HC, however, stated that DDA did receive a complaint about the blocked sewer and asked it to pay the compensation as per law and not just form committees.

THE INDIAN EXPRESS,

Mundka sewer deaths: HC tells DDA to pay Rs 10 lakh compensation to kin of two victims

MALAVIKA PRASAD
NEW DELHI, OCTOBER 6

THE DELHI High Court Thursday directed the Delhi Development Authority to pay compensation of Rs 10 lakh each to the families of two men who died after they inhaled toxic gases inside a sewer at a residential society in Outer Delhi's Mundka last month.

A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was hearing the matter, wherein the DDA had filed a compliance report with respect to the incident. The court observed that "it is very unfortunate that even after 75 years of independence, poor people are being forced to work as manual scavengers and the provisions of Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, and rules framed therein are not being followed".

The counsel for the DDA submitted that the authority has taken a decision to provide compensation to families of the deceased.

The court observed that initially the DDA, in its report, had stated that the workers who died while cleaning the manhole were cleaning it on their own without instructions of the DDA. "It has been stated that no instructions were given by the DDA to clean the manhole, however, at the same time the report reveals that a complaint was received by DDA in respect of blockage in the sewer," the court noted.

The court also directed the DDA to consider the dependent's claim for grant of compassionate appointment in terms of the order of Supreme Court and statutory provisions. It directed DDA to communicate its decision with respect to compassionate appointment of the dependents of the deceased within a period of 30 days to the HC. The court further directed that if the orders of the court are not followed by the authority, then the vice-chairman of the DDA shall remain present in court on the next date of hearing.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Project To Take A Few Million Vehicles Off Roads Picks Pace

CYCLEWALK: DDA To Start Survey Of Land Near JNU Campus

ON COURSE

DELHI CYCLEWALK PROJECT

- **11 lakh** Approximate active cyclists who use roads in the city
- **10km** Typical distance travelled by cyclists
- **200km** Length of dedicated cycle-walk track planned by DDA
- **36km** Length of Phase I of Delhi Cyclewalk project
- **₹550 crore** Estimated project cost
- **2.4 metres** Width of cycle track and walkway
- **1 metre** Width of green strip separating cycle track from walkway

THREE LEGS OF PROJECT'S PHASE I

LEG B Peacock line | 8.5km
Malviya Nagar Metro Station to Vasant Kunj

LEG C Bulbul line | 7km
Chirag Dilli to Sant Nagar and Chirag Dilli to Asiad Village complex

LEG A Nilgai line | 20.5km
Sangam Vihar to Malviya Nagar Metro Station

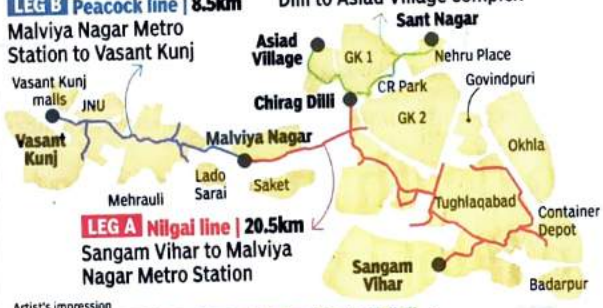

Artist's impression

CYCLEWALK FEATURES

- Cycle tracks
- Pedestrian track
- Universal accessibility track
- Origin and destination plazas
- Intermediate stations
- Land bridges
- Solar lights
- CCTV cameras
- Public toilets
- Rainwater harvesting chambers

STATUS

- Work for Phase-I (Leg A), Nilgai line, has been awarded and architectural consultant appointed in September 2020
- Getting permission for construction of track on non-DDA land in process
- Date of completion as per tender is September 2025 for Phase-I

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Work on the first phase of Delhi Development Authority's ambitious "Delhi CycleWalk", meant for both pedestrians and cyclists, has started gathering pace, with DDA going to start a land survey near the Jawaharlal Nehru University campus in south Delhi.

"DDA has planned to develop about 200km dedicated cycle-walk track to provide pollution-free green commuting. Delhi CycleWalk has been conceived with the objective to take a few million car rides out of the Delhi roads and allow people to walk and cycle safely and joyfully," an official said.

The foundation stone of the project was laid by Union home minister Amit Shah on January 6, 2020. The work on the first leg of Phase I—Sangam Vihar to Malviya Nagar Metro Station—was awarded for on-grade (ground level) cycle-walk in September 2020 and an architectural consultant was also appointed at the same time.

The official said the entire route had been divided in five phases and Phase I is approximately 36km long. Phase I is further divided into three legs, which, apart from the 20.5km-long Leg A called Nilgai Line, includes a 8.5km Leg B called Peacock Line, which connects Malviya Nagar Metro Station and Vasant Kunj, and 7km-long Leg C called Bulbul Line, which will stretch from Chirag Dilli to Sant Nagar and a separate branch from Chirag Dilli to Asiad Village Complex.

"The Phase-I project has been sanctioned by the project sanctioning committee of Urban Development Fund, on grade as well as elevated," the official said. "The permission for the on-grade track on land other than DDA is under progress. The date of completion as per tender is September 2025 for Phase I." DDA kept Rs 28 crore in its budget estimates for 2021-22 and Rs 6 crore has been marked in the budget estimate of 2022-23.

The project is proposed to form a loop around the national capital and connect Metro stations, bus stands, high-density residential areas, business, industrial, recreational and educational districts, master plan greens, and make Delhi a "city of connected forests and lakes".

Apart from cycle and pedestrian tracks, the corridor will boast of features like universal accessibility track, origin destination plazas, intermediate stations, land bridges and other ancillary development work, the official said. DDA has mapped origin and destination points and all "origin destination plazas" are proposed to be interlinked to each other by the tracks for cycling and walking. Both on-grade and elevated tracks shall have greens all along the length to soften the edges.

According to DDA, the corridor will be a safer and greener alternative to mobility that would reduce the vehicular load of the city, and provide cheaper last-mile connectivity.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI | FRIDAY, 7 OCTOBER, 2022

Delhi govt launches anti-dust campaign

Over 500 teams to conduct surprise checks at construction sites

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A month-long anti-dust campaign to check compliance of pollution norms at construction sites was launched in Delhi on Thursday and 586 teams have been formed for their enforcement, Environment minister Gopal Rai said.

Addressing a press conference at his residence in Civil Lines, the minister said the campaign has been launched under the Graded Response Action Plan (GRAP) to combat pollution that has been implemented in the national Capital.

"The anti-dust campaign has begun today in Delhi. As many as 586 teams of 12 government departments and agencies have been formed to check dust pollution at construction sites across the city. This campaign will continue for a month till November 6," Rai said.

These teams will conduct surprise inspections at construction sites to check whether they are complying with the pollution norms.

FILE PHOTO

According to the norms, construction sites larger than 5,000 sqm will have to deploy one anti-smog gun, those larger than 10,000 sqm should have two such guns and sites larger than 15,000 sqm will have to set up three anti-smog guns.

Similarly, sites larger than 20,000 sqm will have to engage four anti-smog guns to combat dust pollution.

Rai said that out of 586 enforcement teams, 33 are from the Delhi Pollution Control Committee, 165 from the Department of Revenue, 300 from the Municipal Corporation of Delhi, 33 from the Delhi Development Authority, 14 from the Delhi Jal Board and six from the Public Works Department, among others.

There are 14-point guidelines that every construction company or agency will have to follow at its sites in the National Capital Region (NCR).

Some of these norms are deploying anti-smog guns, covering construction sites with tin walls and tarpaulin sheets and not leaving construction material uncovered.

Rai said the norms state that stone cutting during construction cannot be done in the open and a wet jetting machine should be used for it.

"The enforcement teams will check if these norms are being followed at construct sites. For any violation of anti-dust norms at construction sites, fines ranging from Rs 10,000 Continued on P4

Anti-dust

to Rs 5 lakh will be imposed by the government as per National Green Tribunal (NGT) guidelines. If there is a serious violation, the government can order a construction site to shut down," he said.

The minister also appealed to Delhiites to actively participate in the fight against pollution.

Authorities in the NCR have been asked to strictly implement measures under the first stage of the GRAP. The action plan includes penal and legal action against polluting industrial units.

Under Stage-I, the Centre's Commission for Air Quality Management (CAQM) recommends stopping construction and demolition (C&D) activities at sites having a plot size equal to or more than 500 sqm that are not registered on the "web portal" of the respective states for remote monitoring of air pollution levels.

Death of two in sewer: HC directs DDA to pay Rs 10 lakh each as compensation

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court on Thursday directed the Delhi Development Authority (DDA) to pay Rs 10 lakh each as compensation to the family of two persons who died after inhaling toxic gases inside a sewer here last month.

A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma remarked that it was unfortunate that even after 75 years of Independence, the poor were forced to work as manual scavengers and asked the DDA, under whose jurisdiction the incident took place, to pay the compensation, as mandated under the law, forthwith.

The bench, also comprising Justice Subramonium Prasad added that the DDA shall also

consider granting compassionate appointment to the family of the deceased persons and sought the presence of the vice chairman of the authority in case the order is not complied with till the next date of hearing. The order was passed on a public interest litigation (PIL) initiated by the court on its own based on a news report of the incident.

A sweeper and a security guard died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer. When the sweeper had gone down to clean the sewer, he fainted and the guard followed to rescue him and he also fell unconscious, the police had said. "It is unfortunate that even after 75 years of Independence, poor people are forced to work as manual scavenger and the (laws on the issue) are not being followed," said the court.

"As the DDA has prima facie resolved to pay compensation, keeping in view the judgement of the Supreme Court, the DDA is directed to pay Rs 10 lakh each as compensation to the family of the two deceased and also to consider their claim to grant compassionate appointment in terms of the Supreme Court judgement and statutory provisions," the order ordered.

"The decision shall be communicated to the court in 30 days. It is made clear that if the order is not complied with, vice chairman of DDA shall remain present in court on the next date of hearing," it added.

The counsel appearing for the DDA informed the court that the deceased were cleaning the drain in the absence of any instructions from them and a committee has been formed in relation to the incident. It was added that "not a single DDA official recommended" the deceased to clean the sewer and the work was outsourced. Asking the DDA to pay the compensation "at the first instance" as per the law and not form "committee after committee", the court observed that responsibility can be decided at a later stage and the authorities were free to take other legal action

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF N पंजाब केसरी ----------DATED---7-10-2022

परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश

सीवर में हुई मौतों पर कोर्ट की डीडीए को फटकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को फटकार लगाते हुए उन दो लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी बीते महीने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब हाथ से मैला ढोने का काम करने को मजबूर हैं। बेंच ने डीडीए, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना हुई थी, को कानून के तहत तत्काल एवं अनिवार्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। बेंच ने यह भी कहा कि डीडीए को इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करना चाहिए। मामले में सुनवाई की अगली तिथि तक आदेश का अनुपालन न होने की सूरत में बेंच ने डीडीए के उपाध्यक्ष को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। यह आदेश घटना से संबंधित एक खबर के आधार पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच द्वारा खुद दायर की गई एक जनहित याचिका पर पारित किया गया है। बता दें कि 9 सितंबर को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में सीवर की सफाई के लिए उतरे एक सफाई कर्मी और उसे बचाने गए सुरक्षा कर्मी की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। बेंच ने कहा कि इस संबंध में लागू कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मुआवजे का भुगतान करने का संकल्प लिया है, इसलिए शीर्ष अदालत के फैसले और वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में उसे दोनों मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए का भुगतान करने और अनुकंपा नियुक्ति देने के उनके दावे पर भी विचार करने का निर्देश जाता है। अगर आदेश पर अमल नहीं किया जाता तो डीडीए उपाध्यक्ष को अगली सुनवाई 14 नवंबर को अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

कंस्ट्रक्शन साइटों पर हुआ नियमों का उल्लंघन तो लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना

दिल्ली में गुरुवार से शुरू हुआ एंटी डस्ट अभियान, 6 नवंबर तक चलेगा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में गुरुवार से एंटी डस्ट अभियान शुरु हो गया जो 6 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 एंटी डस्ट नियम लागू किये जाएंगे। इनका उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है। जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है। इसमें डीपीसीसी की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, एमसीडी की 300 टीम, डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जलबोर्ड की 14 टीम, डीडीए की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, सीपीडब्लूडी की 6 टीम, पीडब्लूडी की 6 टीम, एनडीएमसी की 1 टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता कर कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सीएम केजरीवाल ने 30 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये टीम आज से लगातार निर्माण साइट्स का दौरा करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो। जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगी। उस पर 10 हजार से 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन मिलने पर अधिक रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उलंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में ग्रेप लागू है। 500 वर्ग मीटर और उस से ऊपर के सभी निर्माण/विध्वंस वाले प्रोजेक्ट सीएंडडी पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। बिना पंजीकरण के कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पीयूसी चेकिंग और वाटर स्प्रिंक्लिंग के अभियान की मॉनिटरिंग को तरीके से दिल्ली में लागू किया गया है। ऐसे में लोगों से अपील की है कि कहीं भी अगर उनको निर्माण/विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें। नियमों के तह सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ी करना जरूरी है। धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर ही एंटी स्मोग गन लगाने का नियम था।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

राष्ट्रीय सहारा

आजादी के 75 साल बाद भी गरीब हाथ से मैला उठाने को मजबूर : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब हाथ से मैला उठाने का काम करने को मजबूर हैं। उसने कहा कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (पीईएमएसआर) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह कहते हुए मुंडका इलाके में सीवर के अंदर जहरीली गैस से मरने वाले दो लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है। पीठ ने इस घटना को लेकर उचित कार्रवाई नहीं करने एवं अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं करने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को फटकार भी लगाई है। उसने डीडीए को 30 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान कर उसे सूचित करने को भी कहा है। साथ ही डीडीए से मृतकों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने एवं उसकी जानकारी भी एक महीने में देने को कहा है।

दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का निर्देश

परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करे डीडीए

उसने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो डीडीए के उपाध्यक्ष अगले सुनवाई के दिन पेश होकर स्पष्टीकरण दें। पीठ ने उस घटना के बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

डीडीए के वकील ने कोर्ट से कहा था कि सफाई कराने के जिम्मेवार व्यक्ति ने इन लोगों को निजी तौर पर काम पर रखा था और इसलिए सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। कोर्ट ने डीडीए की खिंचाई करते हुए कहा यह आपके कठोर रवैए की पराकाष्ठा है। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके मे 9 सितम्बर को एक 32 वर्षीय रोहित चांडिलिया की सीवर साफ करते समय मौत हो गई थी। घटना के दौरान पास में तैनात एक सुरक्षा गार्ड 30 वर्षीय अशोक की भी चांडिलिया को बचाने की कोशिश करते समय मौत हो गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE HINDU ----------DATED----------

DDA again extends window for applications to land pooling policy

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has decided to extend the window for accepting applications for its land pooling policy (LPP) by a month, the urban body announced on Thursday. The earlier deadline to submit applications to participate in the LPP was September 30.

According to a senior DDA official, the decision was taken as the urban body has received a lukewarm response from landowners, in the 104 villages identified for the LPP.

From May 28, when DDA reopened the window for the LPP, till September 30, close to 150 applicants, with a total of 115 hectares of land, expressed interest in the policy. The window for the policy has already been extended once – from August 25 to September 30. However, the extension has done little to kindle interest in the policy with most of the land earmarked for LPP still being privately owned.

The senior DDA official added that since 2019, when the window for the LPP applications was first opened, only 7,070 applicants with 7,390 hectares of land have expressed their interest, out of the total poolable land of 19,074 hectares.

DDA to pay ₹10 lakh each as compensation for sewer deaths

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The High Court on Thursday ordered the Delhi Development Authority (DDA) to pay ₹10 lakh each as compensation to the families of two persons who died after inhaling toxic gases inside a sewer here last month.

It also asked the DDA to consider granting compassionate appointment to the kin of the victims and posted the case for hearing on November 14.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | FRIDAY | OCTOBER 7, 2022
DATED

GOVT BEGINS GRAPPLING WITH POLLUTION

Anti-dust drive launched by Rai, 586 teams to check compliance at building sites

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Environment Minister Gopal Rai on Thursday launched a month-long anti-dust campaign to check compliance of pollution norms at construction sites. Rai said that 586 teams have been formed for its implementation.

"Out of these 586 teams, 33 teams came from the DPCC, 165 teams from the Revenue Department, 300 from MCD, 20 from DSIDC, 14 from DJB, 33 teams from DDA, 3 from Delhi Metro, 6 teams each from CPWD and PWD, one team from NDMC, four teams from Delhi Cantonment Board and one team from NHAI," the Delhi Government Minister said while addressing a press conference.

Rai said the campaign has been launched under the Graded Response Action Plan (GRAP) to combat pollution that has been implemented in the national Capital.

"We have collaborated with several agencies to form 586 teams to monitor the implementation of this campaign. These 586 teams will go on the ground to ensure that all the rules made for the construction sites under the anti-dust campaign are being followed," said Rai. "Also, as the GRAP system is in force in Delhi, all the construction sites with an area above 500 sq mt need to register on the portal. If they are not registering themselves, they will be barred from further construction," said Rai. "Moreover, PUC checks and water sprinkling campaigns are being implemented with effective monitoring. The anti-dust campaign will continue for one month and end on November 6. All the 586 teams will actively monitor its implementation on the field. All the construction sites have to follow rules and action will be taken if someone defaults in following them. A penalty between Rs 10,000-Rs 500,000 can be imposed and if there is a serious violation, we will order a shutdown of the construction site," said Rai. According to the norms, construction sites bigger than 5,000 sq mt will have to deploy one anti-smog gun, those bigger than 10,000 sq mt should have two such guns and sites bigger than 15,000 sq mt will have to set up three anti-smog guns. Similarly, sites bigger than 20,000 sq mt will have to engage four anti-smog guns.

"I appeal to the people of Delhi to complain on the Green Delhi app if you come across someone or any construction site not following anti-dust pollution rules in your neighbourhood or anywhere across Delhi. You can complain on the Green Delhi app by clicking photographs. This will help us in monitoring and implementing the campaign better," he added.

Smog tower cut PM2.5 by 17%, PM10 by 27% in 100 m radius

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Central Pollution Control Board (CPCB) data showed that the 82-feet-high smog tower at Anand Vihar reduced PM2.5 concentration by up to 17 per cent in a radius of 100 metres in the winter of 2021-22. The smog tower reduced PM10 pollution levels by up to 27 per cent at a distance of 100 metres during the period. The CPCB said while replying to an RTI.

The smog tower will be used experimentally for two years. Based on the results, the Government will take a call on replicating the project in other parts of the city.

Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, Centre for Science and Environment (CSE), termed the results "insignificant", saying it seems the giant air purifier did not lead to any improvement in air quality beyond 200 metres.

The CPCB data showed the smog tower reduced PM2.5 levels at a distance of 100 metres by 13 per cent in December last year, 7 per cent in March this year and 17 per cent in April. The data pertaining to the decrease in PM2.5 levels at 100 metres for November, January and February was not available. In a radius of 50 metres, the PM2.5 concentration dropped by 39 per cent in November, 24 per cent in December, 22 per cent in January, 10 per cent in March and 23 per cent in April. The data for February and May was not available.

PM2.5 are fine particles that are 2.5 microns or less in diameter and can travel deep into the respiratory tract, reaching the lungs and entering the bloodstream.

Inaugurated in September last year, the smog tower brought the PM10 levels (at 100 metres) down by 27 per cent in December, 16 per cent in March, 23 per cent in April and 15 per cent in May. The CPCB could not share data for November, January and February. At a distance of 50 metres, the PM10 concentration reduced by 50 per cent in November, 41 per cent in December, 26 per cent in January, 21 per cent in March, 32 per cent in April and 13 per cent in May.

"During winter, the monthly average of (PM10) at Anand Vihar is usually above 200 micrograms per cubic metre. The CPCB standard is 60 micrograms per cubic metre and the WHO standard is 15 micrograms per cubic metre. So, at least 70 per cent reduction is needed to meet the CPCB standard and over 90 per cent to meet the WHO norms," Somvanshi said.

The smog tower has 40 fans and 5,000 filters developed by experts at University of Minnesota which also helped design a 100-metre-high smog tower in Xian, China.

The Anand Vihar smog tower was constructed at a cost of Rs 13.59 crore. It is based on a downdraft airflow model. Its 40 huge fans suck air from the top of a special type of canopy structure and release clean air below.

Congress slams AAP for burning Ravan effigies amid pollution

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Congress on Thursday lashed out at the AAP for burning Ravana effigies in the national Capital and said this 'blatant violation' of pollution norms caused the air quality in the city to turn poor.

The AAP on Tuesday burnt effigies of Ravana at around 3,500 locations in Delhi in a symbolic protest against the BJP's 'failure' to maintain cleanliness in the Capital.

'Ravana made of BJP's garbage' was written on all the effigies burnt during the protest. Delhi Congress president Anil Kumar said it was a blatant violation of Commission for Air Quality Management (CAQM) norms.

"The CAQM has put a total ban on burning of waste, use of generators and construction work generating dust, but AAP leaders and workers flouted the guideline and put the lives of Delhiites in danger," he said.